

भारत सरकार
(जनजातीय कार्य मंत्रालय)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या +4688
उत्तर देने की तारीख 22.07.2019

जनजातीय लोगों को आवास

+4688. श्री के. शनमुगा सुंदरम: श्री पी. वेलुसामी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में जनजातियों की संख्या 7.21 लाख है जो कि कुल जनसंख्या का 1.10 प्रतिशत है और अधिकतर जनजातीय समुदाय संरक्षित वनों में रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार तमिलनाडु के जनजातीय लोगों को आवास प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो विशेषकर पोलाची निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का जनजातीय लोगों के आवास हेतु पृथक निधि सृजित करने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)**

(क): जनगणना 2011 के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 7.95 लाख है जोकि राज्य की कुल जनसंख्या का 1.1% है | तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अधिकतर जनजातीय समुदाय वन क्षेत्रों के आस-पास रहते हैं|

(ख) तथा (ग): वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" के सरकार के विजन के अनुसरण में, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणियों के लोगों की आवास आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य / संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) को सहायता प्रदान करने के लिए 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) {पीएमएवाई(यू)} को कार्यान्वित किया गया है | इसी प्रकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को कार्यान्वित कर रहा है | भूमिहीन परिवारों सहित सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) - 2011 के आंकड़ों के अनुसार सभी ग्रामीण परिवारों को जो घर रहित और बेघर, एक और दो कमरों के कच्चे घरों में रहते हैं, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है | वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य है | वर्ष 2018-19 में तमिलनाडु में पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत 1,57,033 घरों का निर्माण पूरा किया गया है | इसके अतिरिक्त 1,71,966 घरों के निर्माण पीएमएवाई-जी के अंतर्गत तमिलनाडु में पूरा किया गया है |

तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार , पिछले तीन वर्षों के दौरान पोलाची निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी घर का निर्माण नहीं किया गया है । तथापि, इस निर्वाचन क्षेत्र में कालिआनकथू गांव में 25 घरों के निर्माण के लिए उनके द्वारा एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो तमिलनाडु सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) & (ड.): जनजातीय आवासन के लिए अलग से कोई कोष बनाने का प्रस्ताव नहीं है।
